



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1479]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 30, 2019/वैशाख 10, 1941

No. 1479]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 30, 2019/VAISAKHA 10, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2019

**का.आ. 1664(अ).**—केंद्रीय सरकार, यह समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है यूरैनियम उद्योग में की सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की प्रथम अनुसूची की प्रविष्टि 19 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवाएं घोषित करती है;

अतः अब केंद्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (ड) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से यह घोषणा करती है कि उक्त उद्योग की सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवाएं होगी।

[फा.सं. एस.11017/9/97-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30<sup>th</sup> April, 2019

**S.O. 1664(E).**—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the services engaged in the Uranium industry which is covered by entry 19 in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares from the date of publication of this notification that the said services in the industry to be a public utility service for the purpose of the said Act for a period of six months.

[F.No. S-11017/9/97- IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.